bining Alphonso with Banganapalli, and I understand that this variety has been named Aruna. I want to know whether commercial production of this variety of mango has started. In case it has already started, what is the share of export of this mango?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I rule out your second supplementary, because that is for the Agriculture Minister. The Minister can answer your first supplementary.

SHRI M. A. BABY: It is about exports—whether this variety is being exported. That comes under Commerce.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If it is produced, it will be exported.

SHRI M. A. BABY: It comes under Commerce. ... *(Interruptions)* ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. I am not permitting any interruptions.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: Madam, so far as the export of mangoes is concerned, I welcome the efforts of all the lobbies, not only Bombay lobby, U.P. lobby, South lobby, North lobby. All the lobbies I welcome. About the Alphonso mango, it has certain very distinct advantages. Firstly, it comes very early in the season. It starts coming from the month of February when our competitor-countries do not have similar mangoes to reach the international market.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer, please. He is saying it by his experience. You are not a mango exporter.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: The availability of Indian mangoes which are available for export, is spread over six months. One after the other different varieties come. So far as Alphonso is concerned, it starts early and it stays for long also. It does not just disappear in one month. It stays longer. For the information of the Members, in addition to Alphonso we have been trying to introduce Banganapalli, Suvarnarekha, Kesar, Chausa, Dassehri and Langda in the international market. In addition to these, we are trying to introduce other varieties also in the international market. ... *(Interruptions)* ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have discussed enough about the varieties of mangoes. Question No. 425, Mr. Iqbal Singh. ... *(Interruptions)*

We are not discussing about the ... *(Interruptions)* ... The question is about the export of mangoes. You can table a question especially for Dassehri. ... *(Interruptions)*.

Let us have a committee of the House to look into the quality and the taste of mangoes.

Recession in automobile sector

*425. SHRI IQBAL SINGH: †
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the automobile sector has recovered from the recessionary trends;

(b) if so, the details thereof company-wise;

(c) the number of workers retrenched by the companies during the last two years;

(d) whether they have been provided with alternative jobs; and

(e) if not, the reasons therefor?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां। भारतीय आटोमोबील विनिर्माता संघ द्वारा अप्रैल से जून 1993-94 की अवधि के लिए दिये गये आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल से जून तक की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विभिन्न किस्म के आटोमोटिव वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये)।

(ग) से (ङ) आटोमोबील क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के दौरान आई मंदी के फलस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी करने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

विवरण

विनिर्माता का नाम	बिक्री	
	अप्रैल	जून
	1992-93	1993-94
मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहन		
टाटा इंजीनि	3287	3478

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Iqbal Singh.

हिन्दुस्तान मोटर्स	4	24
टेल्को	6903	8071
कुल	10194	11573

हल्के वाणिज्यिक वाहन

अशोक लेलैंड	33	10
बजाज टेम्पो	2637	4633
डी॰ सी॰ एम॰ टोयाटा	398	376
आयशर मोटर्स	546	558
हिन्दुस्तान मोटर्स	141	443
महिन्द्रा निस्सान	451	270
महिन्द्रा	693	800
स्वराज माज़दा	512	367
टेल्को	2957	5776
कुल	8368	13233

कारें

हिन्दुस्तान मोटर्स	4148	6077
मारूती उद्योग	23699	35736
प्रीमियर आटो	4455	4023
टेल्को	376	1328
कुल	32678	47164

जीपें

महिन्द्रा	8214	8741
मारूति उद्योग	926	1001
कुल	9140	9742

स्कूटर्स

बजाज आटो	110128	112644
गुजरात नर्मदा	110	0
केल्वीनेटर	29	108
काईनेटिक होंडा	23106	18666
एल॰ एम॰ एल॰	15384	31735
महाराष्ट्र स्कूटर्स	25182	24325
स्कूटर्स इंडिया	623	348
कुल	174562	187826

मोटारसाइकिल्स

बजाज आटो	24361	30559
एनफील्ड	4713	4665
एस्कोर्टस	30187	29279
हीरो होंडा	29224	34076
आइडियल जावा	0	40
टी॰ वी॰ एस॰ सुजुकी	5427	8837
कुल	93912	107456

मोपेड्स

बजाज आटो	14135	13020
एनफील्ड	291	833
केल्वीनेटर	3401	1131
काइनेटिक इंजी॰	27056	27790
काइनेटिक होंडा	4026	4436
मेजेस्टिक आटो	16721	24363
टी॰ वी॰ एस॰ सुजुकी	29310	31244
कुल	94940	102817

तिपहिये

ए॰ पी॰ आई॰	783	0
बजाज आटो	12563	16967
स्कूटर्स इंडिया	931	676
कुल	14277	17643

श्री इकबाल सिंह : मैडम, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस साल का जो बजट था वह बहुत ही सराहनीय था, उसमें एक्साइज और कस्टम दोनों ड्यूटीज कम कर दी गयी थीं, लेकिन उसके बावजूद यह देखा गया है कि ऑटोमोबाइल में प्राइसेस बढ़ रही हैं, गाड़ियों की कीमत बहुत आगे जा रही है, खास तौर से टू-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स की । साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इतना अच्छा बजट होने के बावजूद जब कस्टम और एक्साइज ड्यूटीज कम हो गयी हैं तो फिर कंपनियां क्यों बंद हो गयी हैं ? मालवीया, इन्होंने अपने उत्तर में ही बताया है कि कंपनियों में बट्टोत्तरी हुई है और गाड़ियों की बट्टोत्तरी हुई है, लेकिन देखने में यह आता है कि एनफील्ड और महेन्द्रा निशान व प्रीमियम ऑटो, इस तरह की 10 कंपनियां बहुत कम प्रोडक्शन कर रही हैं और उनकी बिक्री भी कम हो रही है । दूसरे, इसमें यह देखा गया है कि कुछ कंपनियों में स्टाइक भी चल रही है जिससे कि कर्मचारियों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है । तो इस संबंध में मंत्री जी बताएं कि कीमत

क्यों बढ़ रही है और जो कर्मचारी हैं, उनके बारे में वे क्या सोच रहे हैं?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, वर्ष 1993-94 के बजट में मोटरगाड़ी उद्योग के लिए आयात शुल्क को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था तथा फ़्यूएल एफीशिएंट हल्के वाणिज्यिक वाहनों के कम्पोनेंट्स के लिए आयात शुल्क मात्र 25 प्रतिशत है । यह बात सही है कि एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया, 55 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया था और निजी वाणिज्यिक वाहनों एवं लिपड़िया वाहनों के लिए इसे 23 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया । मैडम, ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए यह काम किया गया था और बजट के बाद विभिन्न मॉडल्स की गाड़ियों के दामों में 15 से 35 हजार की कमी भी आयी थी । लेकिन 1993-94 के बजट में एक्साइज ड्यूटी के फलस्वरूप आमतौर पर वाहन निर्माताओं ने अपनी वाहनों की कीमतें भी उसी अनुपात में घटा दीं, परन्तु बाद में कुछ निर्माताओं ने इसमें वृद्धि की है । सवारी कारों के क्षेत्र में टेल्को, हिन्दुस्तान मोटर तथा वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में टेल्को और अशोक लेलैण्ड ने कीमतें बढ़ाई हैं । और भी कुछ है, जिनकी माननीय सदस्य ने चर्चा की है । तो यह बहुत लंबी लिस्ट है, अगर वह चाहेंगे तो मैं उनको वह सूची बाद में भेज दूंगी ।

उपसभापति : नहीं, वह पूछ रहे हैं कि क्यों बढ़ाई है ? वह पूछ रहे हैं ।

श्रीमती कृष्णा साही : यह जो वृद्धि की है, इसमें निर्माताओं का कहना है कि मुद्रास्फिति के कारण इनपुट्स की लागत में वृद्धि हुई है, जिसके चलते उन्हें दाम बढ़ाने पड़े हैं । नियंत्रण हम लोगों का इसलिए नहीं रहता क्योंकि बोर्ड आफ डायरेक्टर है और बोर्ड आफ डायरेक्टर जो हैं वही इसमें निर्णय लेते हैं । सरकार को है इसके ऊपर जानती आवश्य है कि जो ग्राहक है उनको सुरक्षा मिले और वित्त मंत्री ने घोषणा भी की थी कि यदि एक्साइज ड्यूटी का रिडीफ कंज्यूमर को नहीं मिलेगा तो पुन: यह शुल्क बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं । बजट के बाद ले निश्चित रूप से यह लाभ हुआ था । सरकार अपेक्षा करती है कि ग्राहकों के प्रति अन्याय नहीं होगा । बोर्ड आफ डायरेक्टर ने इस पर निर्णय लेना है : इसके लिए सरकार उनसे अपील करेगी कि इस तरह का निर्णय वृद्धि का न लें । नियंत्रण पर कोई कानूनी हमको अधिकार नहीं है, न इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता है । सरकार की नीति है कि अनेक मोटरवाहन उपलब्ध हों, बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण वाहनों की कीमतों, उनकी गुणवत्ता, उस पर नियंत्रण रहे, लेकिन यह कीमत का बोर्ड आफ डायरेक्टर निर्णय लेती है । वह स्वतंत्र है । हम अपेक्षा करते हैं कि ग्राहकों के प्रति अन्याय नहीं होगा ।

श्री इकबाल सिंह : मैडम, क्या मंत्री महोदय बताएंगे, क्या वह ऐसी कोई पालिसी बनाएंगे कि ग्राहक को उसमें फायदा हो और डायरेक्टर के ऊपर कोई ऐसा रूल लगाया जाए कि जब एक्साइज, कस्टम कम हो गया तो ग्राहक कंट्रोल किया जाए किसी ढंग से ? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई नई पालिसी आप बना रहे हैं मंत्री जी, जिससे व्हीकल आटोमोबाइल में किसी ढंग से तरक्की हो सके, उन्नति हो सके?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, नई औद्योगिक नीति के तहत कारों को छोड़कर बाकी आटोमोबाइल वाहनों को 24 जुलाई, 1991 से लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है और कारों को भी अप्रैल, 1993 से लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है । अत: यह संपूर्ण आटोमोबाइल क्षेत्र अब लाइसेंस-मुक्त हो गया है । अभी तो कोई दूसरी पालिसी नहीं है, जो नई हमारी औद्योगिक पालिसी बनी है, उसी के तहत यह आटोमोबाइल पालिसी भी हमारी है ।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, प्रश्न बड़ा सीधा था कि आटोमोबाइल व्हीकल का प्रोडक्शन प्राय: गिर रहा है और आटोमोबाइल व्हीकल की कीमतों में वृद्धि भी प्राय: देखने को मिल रही है, तो आटोमोबाइल व्हीकल का प्रोडक्शन न गिरे और आटोमोबाइल व्हीकल की कीमतों में वृद्धि न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रबंध किये जा रहे हैं? क्या कोई प्रबंध किया जा रहा है या नहीं?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, यह तो मैंने इनको जो उत्तर दिया है उसमें आनेक्स भी किया है कि हमारी सेल तो बढ़ रही है । यह बात सही है कि चतुर्दिक आटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ोत्तरी हुई है, केवल दो सेक्टर में उत्पादन कुछ कम हुआ है, लेकिन दाम, ग्राहक तो मिल रहा है । हमारी समझ में इसमें प्रथम तिमाही में ट्रैक्टर को छोड़कर सभी वाहनों में बिक्री बढ़ी है । ....

उपसभापति : नहीं, आप इसमें कुछ निर्णय ले रहे हैं कि यह वृद्धि न हो कीमतों में और प्रोडक्शन न कम हो ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, जैसा मैंने कहा कि मूल्य नियंत्रण पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम उन्हें दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि ग्राहकों के प्रति अन्याय न हो ।

उपसभापति : कोई कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है आपकी तरफ से?

श्रीमती कृष्णा साही : वह दूसरे विभाग से संबंधित है कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन का ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : If it is a consumer? Anybody who buys a car is a consumer.

DR. NAUNIHAL SINGH : We are talking here on the question of the recessionary trends in the automobile industry. In order to do away with the recessionary trends in the automobile industry, you think not only of domestic sales, but also of exports, as potent instruments. In

this context I would like to ask the hon. Minister or the Prime Minister whether the Government has made any effort to export automobile parts. If so, to which country and what was its volume in terms of dollars and rupees during the year 1992-93?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Pending cases in Supreme Court relating to reservation of SC/STs

*422. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total number of cases relating to reservation of SC/STs pending in Supreme Court, as on 1-8-1993, for more than one year, for more than five years, for more than ten years and for more than fifteen years, separately;

(b) whether the Supreme Court proposes to constitute a special bench for deciding all the matters relating to reservation of SC/STs within a limited period keeping in view the Government policy; and

(c) the total number of Government counsels at present for Supreme Court working on behalf of Central Government and number of SC/STs therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) As per the information made available by the Registry of the Supreme Court, 83 cases relating to reservation of SCs/STs were pending as on 1st August, 1993. The break-up is as follows:

More than 1 year	—	83 cases
More than 5 years	—	80 cases
More than 10 years	—	63 cases
More than 15 years	—	1 case

(b) The above matters are already before the Constitution Bench of the Supreme Court.

(c) Of the 10 full time Advocates working for the Government in the Supreme Court, one belongs to SC category.

गुजरात में बंजर भूमि के विकास संबंधी स्वैच्छिक एजेंसियों का पता लगाया जाना

*426. श्री रामसिंह राठवा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में बंजर भूमि के विकास संबंधी स्वैच्छिक संगठनों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) उनकी सेवाओं का कब तक उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये इन स्वैच्छिक संगठनों के पूर्व कार्यों की समीक्षा की है कि कहीं इन संगठनों के विरुद्ध विगत में सरकारी धन का दुरुपयोग करने की शिकायतें तो नहीं की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास) में राज्य मंत्री (श्री कमल राम सिंह): (क) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की अनुदान-सहायता योजना के अन्तर्गत गुजरात सहित देश में बंजर भूमि के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों का पता लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, बंजर भूमि के विकास के लिए सहायता चाहनेवाले स्वैच्छिक संगठन अपनी ओर से राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को आवेदनपत्र देते हैं और अनुदान-सहायता योजना के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वैच्छिक संगठनों, जिनमें गुजरात के संगठन भी शामिल हैं, से अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों की टिप्पणी प्राप्त कर लेने के बाद अनुमोदित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अनुदान-सहायता योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन की भी व्यवस्था है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संगठनों को रिलीज की गई धनराशि का समुचित ढंग से उपयोग किया गया है।

Ban on Benzidine and Benzidine-based Dyes

*427. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the manufacture, marketing and use of Benzidine and Benzidine-based dyes were banned with effect from January 31, 1993 on account of their carcinogenic nature;

(b) whether it is also a fact that despite the Government giving more than three years time before imposing the ban to the manufacturers and users, Benzidine-based dues continue to be manufactured, sold and used even after the ban has become effective; and